भाजपा सरकार फैसले लेकर बार-बार पलट रही, इनकी उल्टी गिनती शुरू : सचिन पायलट

पायलट ने कहा कि, ''केन्द्र सरकार कंफ्यूज्ड और बैकफुट पर हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से धनतेरस की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात कर पंच दिवसीय दीपोत्सव की बधाई दी।

पायलट ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, '' केंद्र की भाजपा सरकार गंभीर मुद्दों पर पहले फैसले करती है और फिर दबाव में उन्हें वापस ले लेती है। कृषि कानून, जातिगत जनगणना और अग्निवीर योजना इसके उदाहरण हैं।

सरकार की इस कार्यशैली से उसकी असहजता और भ्रम की स्थिति उजागर हो रही है। देश में युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक को लेकर गहरा असंतोष है, जबकि किसान भी परेशान हैं। भाजपा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोग बदलाव चाहते है।''

जयपुर में मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने डेढ़ साल तक आंदोलन किया, सैकड़ों लोगों की जान गई, तब सरकार को कानून वापस लेने पड़े।

राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। पहले उन्हें अर्बन नक्सली कहा गया और बाद में सरकार खुद इसके समर्थन में आ गई। अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को अपने फैसलों में बदलाव करना पड़ रहा है।

सवाल है कि स्थायी सैन्य भर्ती व्यवस्था क्यों बदली गई और अब योजना में बदलाव किस दबाव में किए जा रहे हैं? सरकार न तो फैसला लेने का आधार बताती है और न उसे वापस लेने का कारण।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से धनतेरस की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने परिवारजनों के साथ मुलाकात की।

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि कानूनों, जातिगत जनगणना और अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को घेरा

13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला

सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद, फॉर्म-16 में बदलाव और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद अब सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए 13.5 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की कोशिश गंभीर मामला है। वोट का अधिकार लोकतंत्र का सबसे मूलभूत अधिकार है। इससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और ईडी, सीबीआई तथा नौकरशाही का दुरुपयोग हो रहा है।

पंजाब में कांग्रेस-आप के बीच होगा मुकाबला

पंजाब चुनाव पर सचिन पायलट ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है और पार्टी में जल्द बिखराव होगा। सात-आठ राज्यसभा सांसदों के एनडीए में जाने और विधायकों के पार्टी छोड़ने से आप के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और आतंकवाद से मुक्ति दिलाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। संगरूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के विरोध और बल प्रयोग के बावजूद लाखों लोग पहुंचे।

पायलट ने कहा कि केंद्र में 12 साल से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा पंजाब को कोई विशेष पैकेज, बड़ा उद्योग या निवेश नहीं दे पाई। पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए आने वाले हथियारों और नशीले पदार्थों को रोकने के लिए भी सरकार को जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सोशल मीडिया पर चर्चा करने के बजाय अपने नेतृत्व को आत्मचिंतन की सलाह देनी चाहिए। सत्ता का अहंकार छोड़कर सरकार को युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए। राहुल गांधी ने अब तक जो मुद्दे उठाए हैं, वे सच साबित हुए है।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक टाऊनशिप का विस्तार होगा

300 हैक्टेयर से अधिक जमीन पर विकसित होंगे नए उद्योग

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत विकसित हो रहे जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) को राजस्थान की विशिष्ट एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में तैयार किया जा रहा है। निवेशकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया और विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए इसके उत्तरी हिस्से में 300 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। यहां पर्यावरण अनुकूल एवं कम प्रदूषणकारी उद्योगों के साथ आवासीय और भंडारण सुविधाएं भी विकसित होंगी।

रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में गुरुवार को उद्योग भवन में हुई बैठक में परियोजना की प्रगति, निवेशकों की प्रतिक्रिया और उत्तरी हिस्से के विस्तार की योजना की समीक्षा की गई। बैठक में रीको सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पाली जिले के रोहट में विकसित हो रही इस टाउनशिप में औद्योगिक इकाइयों के साथ आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और सामाजिक सुविधाओं का भी नियोजित विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योगों, उद्यिमयों, श्रमिकों और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाओं वाला औद्योगिक परिवेश उपलब्ध कराना है। पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के साथ व्हाइट और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- इस औद्योगिक टाउनशिप से पश्चिमी राजस्थान में निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद : सुरेश कुमार ओला

उत्तरी हिस्से की विस्तृत योजना शीघ्र अंतिम रूप दी जाएगी। इसके बाद लागत आकलन तैयार कर इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। कार्य पूरा होने पर भूमि निस्तारण नीति के अनुसार भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

20 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

परियोजना के प्रथम चरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए निवेशक 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। पहले दौर में 30 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। अगले दौर में और भूखंड आवंटन के लिए खोले जाएंगे। मोटल, रेस्टोरेंट सहित औद्योगिक एवं सामाजिक सुविधाओं के भूखंडों का प्रत्यक्ष आवंटन भी शुरू हो चुका है।

पानी-बिजली की सुविधाओं पर काम तेज

प्रथम चरण में प्रमुख सड़कों और आधारभूत ढांचे का विकास तेजी से किया जा रहा है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से परियोजना स्थल तक जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जा रही है। वहीं, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कांकाणी से परियोजना सीमा तक डबल-बे लाइन बिछा रहा है। रीको विकास कार्यों की नियमित निगरानी कर रहा है।

इस औद्योगिक टाउनशिप से पश्चिमी राजस्थान में निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

बार उपाध्यक्ष सुनील शर्मा को पीएचडी की उपाधि



जयपुर। निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के उपाध्यक्ष एवं जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है।डॉ. सुनील कुमार शर्मा ने ''मानव संसाधन प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता : कानूनी, नैतिक एवं प्रबंधकीय चुनौतियां'' विषय पर डॉ. अनुपमा मिश्रा पांडे के निर्देशन में शोध पूरा किया। शोध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कानूनी एवं प्रबंधन क्षेत्र में उपयोग, उससे जुड़ी कानूनी, नैतिक और प्रबंधकीय चुनौतियों तथा विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण किया गया है। यह अकादमिक उपलब्धि हासिल करने पर बार एसो. के अधिवक्ताओं, परिजनों और शुभचिंतकों ने डॉ. शर्मा को बधाई दीं।

आरजीएचएस में काम करवाने के नाम पर मांगा 10 लाख रु. कमीशन

- टीपीए इंचार्ज बताकर कोटा के एक निजी हॉस्पिटल प्रबंधन को धमकाकर लाखों रुपए मांगने का मामला सामने आया
- आरोपी ने हॉस्पिटल पर अतिरिक्त पेनल्टी लगवाने और कार्रवाई करवाने की धमकी देकर छह लाख रुपए मांगे थे, जयपुर के अशोक नगर थाने में मामला दर्ज

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। खुद को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) का टीपीए इंचार्ज बताकर कोटा के एक निजी हॉस्पिटल प्रबंधन को धमकाने और लाखों रुपए मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने हॉस्पिटल पर अतिरिक्त पेनल्टी लगवाने और कार्रवाई करवाने की धमकी देकर छह लाख रुपए मांगे। वहीं, आरजीएचएस और आयुष्मान भारत योजना में हॉस्पिटल का काम करवाने के नाम पर हर महीने 10 लाख रुपए कमीशन की मांग की। पीड़ित हॉस्पिटल प्रबंधन की शिकायत पर अशोक नगर थाना पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला कोटा के बोरखेड़ा थाने भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार कोटा पुलिस लाइन के पास स्थित शिव शक्ति हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक ने शिकायत दी कि रोहन सिंह नाम का व्यक्ति उन्हें लगातार फोन कर रहा था। कॉल करने वाले ने खुद को आरजीएचएस टीपीए इंचार्ज बताते हुए कहा कि आरजीएचएस और आयुष्मान योजना से जुड़ी टीपीए की सभी कार्रवाई उसकी टीम देखती है। उसने यह भी दावा किया कि उसके कहने पर हॉस्पिटल का आरजीएचएस टीएमएस ब्लॉक करवाया गया है और वह आगे भी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है।शिकायत के मुताबिक आरोपी ने हॉस्पिटल प्रबंधन को बताया कि उनके खिलाफ पेनल्टी निकलवाई गई है और कार्रवाई से जुड़े एक-दो अन्य पत्र भी तैयार हैं। उसने छह लाख रुपए नहीं देने पर एक और कार्रवाई की फाइल आगे बढ़वाने तथा पहले से लगी पेनल्टी पर अतिरिक्त जुर्माना लगवाने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि रकम नहीं देने पर हॉस्पिटल का टीएमएस चालू नहीं होने दिया जाएगा।

'भोजन की बर्बादी रोकना भी पर्यावरण संरक्षण'

जयपुर। पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के लिए सतत खाद्य प्रणालियां अपनाना समय की जरूरत है। भोजन की बर्बादी रोकना, स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना और संतुलित आहार अपनाना ऐसे छोटे लेकिन प्रभावी कदम हैं, जिनसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम किया जा सकता है। यह बात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बुधवार को मंडल मुख्यालय में आयोजित जागरूकता सत्र में कही। 'ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह-2026' के चौथे दिन 'सतत खाद्य प्रणालियां अपनाने' विषय पर आयोजित सत्र में राजस्थान हॉस्पिटल की आहार विशेषज्ञ डॉ. अंशु ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खाद्य आदतों और पर्यावरण के बीच संबंध की जानकारी दी। उन्होंने पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, स्थानीय और मौसमी उत्पादों के उपयोग, जरूरत के अनुसार भोजन लेने तथा खाद्य अपव्यय रोकने पर जोर दिया। कपिल चंद्रवाल ने कहा कि खाद्य पदार्थों के चयन से लेकर उनके उपभोग तक जिम्मेदार व्यवहार अपनाना जरूरी है।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 5 साल बाद बढ़ा नामांकन, 48358 नए विद्यार्थी जुड़े

''शिक्षा सेतु'' अभियान का असर यह रहा कि प्रदेश में कुल नामांकन 72.98 लाख के पार हुआ

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान और विभागीय नवाचारों के चलते पांच साल बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2026 तक सरकारी विद्यालयों में कुल नामांकन 72,98,854 पहुंच गया, जो वर्ष 2025-26 के 72,50,496 नामांकन से 48,358 अधिक है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव के निर्देशन एवं प्रभावी निगरानी में शिक्षा व्यवस्था को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए 'स्टार टीचर' पहल भी शुरू की गई है। इसके तहत 26 अक्टूबर को जारी पहली सूची में आठ सरकारी विद्यालयों के 15 शिक्षकों को राजस्थान के पहले स्टार टीचर के रूप में चुना गया है।

इनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट (सीबीए) में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 11 और नवाचारी शिक्षण पद्धितयां अपनाने वाले 4 शिक्षक शामिल हैं।

- उत्कृष्ट परिणाम और नवाचार पर 15 शिक्षक बने पहले ''स्टार टीचर''

चयनित शिक्षकों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए गए हैं और सूची शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। अब हर महीने उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन होगा।

बालिकाओं का नामांकन 4.86 लाख अधिक

सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन में 53.3 प्रतिशत यानी 38,92,355 बालिकाएं और 46.7 प्रतिशत यानी 34,06,486 बालक हैं। प्रत्येक 1,000 बालकों पर 1,143 बालिकाएं नामांकित हैं। जिलेवार वृद्धि में बांसवाड़ा 11,939, उदयपुर 9,448, बाड़मेर 5,937, जालोर 5,485 और सिरोही 4,295 नामांकन के साथ आगे रहे हैं।

हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का अभियान

राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान दो चरणों में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक प्रधानाचार्य एक शिक्षक को एक बच्चे की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जो परिवार से संपर्क कर उसका नामांकन सुनिश्चित करेगा। शाला दर्पण पोर्टल और डैशबोर्ड से निगरानी की जा रही है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर हर 15 दिन में समीक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रगति की निगरानी और जिला कलेक्टर द्वारा मासिक समीक्षा की जा रही है।अभियान में बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, प्रवासी, बाल श्रमिक, आदिवासी और घुमंतू समुदाय के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन जिलों में नामांकन घटा है, वहां पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या रोकने के लिए विशेष समीक्षा की जा रही है। इन प्रयासों से प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 का समापन

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। भारत मंडपम में भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 के समापन समारोह में गुरूवार को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने यह पुरस्कार प्रदान किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता तथा ऊर्जा विभाग की संयुक्त सचिव नित्या ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद तथा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी की महत्वपूर्ण उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की अग्रणी भूमिका की सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अब तक 51.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। जिसमें से 28 गीगावॉट क्षमता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार के विगत 34 माह में ही स्थापित हुई है।

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के मूल्यांकन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मूल्यांकन तंत्र विकसित किया है। जिसमें राज्यों के प्रदर्शन के लिए 6 प्रमुख मानक बिन्दु तय किए गए है। इन बिन्दुओं, स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, इसके विकास के लिए नीतिगत और नियामकीय ईकोसिस्टम तैयार करने, ग्रिड की तैयारी एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसके सुदृढीकरण, डिस्कॉम्स के प्रदर्शन तथा निवेश के अनुकुल माहौल के आधार पर राजस्थान का प्रदर्शन श्रेष्ठ राज्य के रूप में रहा। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष सारंगी ने मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास को लिखे पत्र में भारत के एनर्जी ट्रान्जिशन तथा 500 गीगावॉट हरित ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान के योगदान को महत्वपूर्ण बताया था।

ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने इस उपलब्धि पर ऊर्जा विभाग एवं इससे जुड़ी सभी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों, समर्पण, प्रतिबद्धता एवं बेहतर समन्वय का परिणाम है।



भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने राजस्थान के ऊर्जा विभाग को सम्मानित किया। मंत्री हीरालाल नागर व राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी रोहित गुप्ता तथा संयुक्त सचिव नित्या ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

- उपराष्ट्रपति से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों के साथ ग्रहण किया पुरस्कार
- नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मूल्यांकन तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला अवार्ड

युवक कांग्रेस के 12 जिला अध्यक्ष और 31 पदाधिकारी निलंबित

जयपुर (कासं)। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर से आयोजित रैली में अनुपस्थित रहने पर राजस्थान युवक कांग्रेस के 12 जिला अध्यक्षों और 31 पदाधिकारी को निलंबित किया गया है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु की ओर से जारी आदेश में जिन 12 जिला अध्यक्षों को निलंबित किया गया है, उनमें राजसमंदके जिला अध्यक्ष चिराग पालीवाल, जालौर के जिला अध्यक्ष विकास मंजू, बीकानेर के जिला अध्यक्ष राजेश गोदारा, बारां जिला अध्यक्ष रामेश्वर बेरवा, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज मालवीय, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, बीकानेर ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामदयाल बेनीवाल, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील, बालोतरा जिला अध्यक्ष सुरेश माली, डीग जिला अध्यक्ष हसन खान, चूरू जिला अध्यक्ष आसिफ खान और ब्यावर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिखवाल शामिल है। इसी तरह से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु ने राजस्थान युवा कांग्रेस के जिन 31 पदाधिकारी को निलंबित किया है, उनमें प्रकाश चंद मीणा, सद्दाम हुसैन, फैजान हसन कुरैशी, जफर हुसैन मीर, सलमा पीनारा, रामफूल धाकड़, गणेश देवासी, ठाकुर बिश्नोई, मंजुला देसाई, अर्जुन सिंह बोचावत, दीपकमेघवाल, आशीष बेरवा, हिमांशु शर्मा, दिनेश कुमार गुर्जर, सुरेश गोदारा, नवाब खान, संग्राम सिंह गुर्जर, मुजाहिद कुरैशी, हुकमाराम, भारत मीणा, महबूब खान, भेराराम पटेल, गनी एमडी सिंधी, रविकांत, गिरिराज कुमार, हिमांशु धाकड़, सुरेश कुमार गुर्जर, अरविंद योगी, विष्णु कुमार मीणा, आसिफ खान और पवन कुमार जांगिड़ शामिल है।

